

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1756  
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है।  
19 अग्रहायण, 1947 (शक)

**डेटा सेंटर सर्वर और हार्डवेयर का आयात**

**1756. श्रीमती स्मिता उदय वाघः  
श्री बलभद्र माझीः**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित सर्वरों का कुल मूल्य और संख्या तथा इन आयातों में योगदान देने वाले प्रमुख स्रोत देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) डाटा-सेन्टर हार्डवेयर आवश्यकताओं का वर्तमान में स्वदेशी निर्माण के माध्यम से पूरा किया जा रहा अनुपात और आयात की तुलना में यह आयात-स्वदेशी उत्पादन अनुपात गत पांच वर्षों के दौरान किस प्रकार परिवर्तित हुआ है;
- (ग) डाटा-सेन्टर अनुप्रयोगों के लिए उच्च क्षमता वाले सर्वरों, भंडारण प्रणालियों एवं संबंधित घटकों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा योजनाओं या नई पहलों के अंतर्गत सरकार द्वारा किये गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने देश की डिजिटल अवसंरचना के लिए आयातित सर्वर हार्डवेयर पर निर्भरता से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं, रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों का कोई आकलन किया है;
- (ङ) यदि हाँ, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ करने एवं महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करने के लिए प्रस्तावित किसी विशेष प्रोत्साहन, टैरिफ परिवर्तन या नीतिगत हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ङ): सरकार सर्वरों और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के आयात की सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों के प्रति पूरी तरह सचेत है। एआई के लोकतंत्रीकरण और गणना क्षमता का विस्तार करने के लिए भारत के प्रयास के साथ, एक अनुकूल नीति व्यवस्था के तहत डेटा केंद्रों की मांग तेजी से बढ़ी है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम) इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, सरकार ने ईसीएमएस, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई, स्पेक्स और ईएमसी/ईएमसी 2.0 जैसी कई पहलें शुरू की हैं। डेटा-सेन्टर बुनियादी ढांचे में सर्वर, नेटवर्किंग डिवाइस, स्टोरेज और कूलिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। इस संबंध में भारत सरकार की प्रासंगिक नीतियां इस प्रकार हैं:

## **आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना**

यह योजना सर्वर, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन (एआईओ) पीसी और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है।

## **इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)**

ईसीएमएस ऑप्टिकल ट्रांसीवर और सर्वर, राउटर और नेटवर्किंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटकों को कवर करता है। सरकार को इनके निर्माण के लिए उद्योग से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

## **दूरसंचार उपकरणों के लिए दूरसंचार विभाग पीएलआई योजना**

दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना, राउटर, स्विच और अन्य नेटवर्किंग गियर के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जो डेटा-सेंटर और सर्वर बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है।

आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए, सर्ट-इन ने जुलाई 2025 में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एआई, क्वॉंटम और क्रिप्टोग्राफी घटकों के लिए तकनीकी बीओएम दिशानिर्देश जारी किए।

इन सरकारी नीतियों और पहलों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में ~1.9 लाख करोड़ रुपये से छह गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ~11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है और इसी अवधि के दौरान निर्यात ~ 0.38 लाख करोड़ रुपये से आठ गुना बढ़कर ~ 3.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

नतीजतन, वैश्विक और घरेलू कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं। घरेलू कंपनियों के सर्वर, नेटवर्किंग उपकरणों और उपकरणों के निर्माण के लिए क्षमता और योग्यता में वृद्धि हुई है जो इनके निर्माण में उपयोग में आते हैं। भारतीय कंपनियां अब वैश्विक ओईएम के साथ-साथ घरेलू ब्रांडों के लिए सर्वर का निर्माण कर रही हैं।

\*\*\*\*\*